'ट्रम्प और हैरिस दोनों शैतान हैं, दोनों में से जो कम बुरा है उसे वोट करें'

ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रैंसिस ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों पर अपना बयान दिया

- पोप ने कहा, ट्रम्प ने अप्रवासी विरोधी नीतियों का समर्थन किया तथा कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति रहते गर्भपात के अधिकारों का खुला समर्थन किया था, दोनों ही उम्मीदवार जीवन के खिलाफ हैं तथा दोनों ही शैतान हैं।
- पोप ने अपने बयान को विस्तार से समझाते हुये कहा, एक आप्रवासियों को त्याग देता है एक वह है जो बच्चों को मारता है, दोनों ही प्रत्याशी जीवन के खिलाफ हैं।

नई दिल्ली, 14 सितम्बर। ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरू पोप फ्रैंसिस ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि डॉनल्ड ट्रम्प की अप्रवासी विरोधी नीतियों और कमला हैरिस के गर्भपात अधिकारों के लिए समर्थन का हवाला देते हुए शुक्रवार को कहा कि दोनों ही उम्मीदवार जीवन के खिलाफ हैं, दोनों ही शैतान है। अब अमेरिका की जनता को तय करना है। उन्हें जो भी उम्मीदवार कम दुष्ट लगे वह उसे अपने विवेक के आधार पर चुनें।

एशिया के अपने 12 दिवसीय दौरे के बाद रोम वापस लौट रहे पोप से जब मीडिया कर्मियों ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि दोनों ही जीवन के खिलाफ हैं। एक आप्रवासियों को त्याग देता है एक वह है जो बच्चों को मारता है, दोनों ही प्रत्याशी जीवन के खिलाफ है।

पोप ने कहा कि मैं अमेरिका का निवासी नहीं हूं और मैं वहां मतदान नहीं करूंगा। लेकिन यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रवासियों को देश में आने की इजाजत नहीं देना , उनको काम न करने देना, उनका स्वागत नहीं करना या फिर गर्भपात का समर्थन करना यह सब पाप ही है।

दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रम्प को उनकी अप्रवासी विरोधी नीतियों के लिए जाना जाता है। उन्होंने हाल ही में अवैध अप्रवासियों को पकड़ने और उन्हें निर्वासित करने का वादा किया है, जबकि दूसरी उम्मीदवार कमला हैरिस ने एक कानून के जरिए महिलाओं गर्भपात करने का अधिकार बना दिया था। हैरिस को इस कानून का समर्थनकर्ता माना जाता है और उन्होंने इसे बहाल करने का वादा किया है।

पोप ने कहा कि दो बुराइयों में से कम को चुनना होगा। इन दोनों में से कौन कम है, वह महिला या वह सज्जन? मुझे नहीं पता। मेरा कहना यही है कि अमेरिका कि जनता को अपने विवेक के आधार पर चुनना होगा और जो कम दुष्ट हो उसको चुनना होगा।

अमेरिका में अगले नवबंर में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। उसकी प्रक्रिया चल रही है। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प उम्मीदवार है तो वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस उम्मीदवार है। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से पहले वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन उम्मीदवार थे लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी के दवाब और स्वास्थ कारणों के कारण अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। इसके बाद यह चुनाव डोनाल्ड ट्रम्प और कमला हैरिस के बीच की सीधी लड़ाई बन गया है।

कश्मीरः शनिवार को मुठभेड़ में तीन आतंकी मारे गये

- गत शुक्रवार को किश्तवाड़ में मुठभेड़ में दो जवानों की शहादत की बदला सुरक्षाबलों ने पांच आतंकियों को मारकर लिया।

श्रीनगर, 14 सितम्बर। जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। बारामूला जिले में शनिवार सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में तीन आतंकवादियों की मौत हो गई, सूत्रों ने यह जानकारी दी है। गौरतलब है कि आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष खुफिया सूचना के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन शुरू किया गया। शुक्रवार देर रात उत्तरी कश्मीर जिले के पट्टन इलाके के चक टापर क्रीरी में गोलीबारी शुरू हुई। वहीं, एक अलग मुठभेड़ में सेना की राइजिंग स्टार कोर इकाई के जवानों ने शुक्रवार को कठुआ में दो आतंकवादियों को मार गिराया था। पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार इलाके में तलाश अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर गोलीबारी की।

बंगालः प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने प्र.मंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखा

डॉक्टरों ने आर.जी. कार मैडिकल कॉलेज मामले में दखल देने की गुहार लगाई

- गौरतलब है कि डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में जूनियर डॉक्टर 35 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने बारिश के दौरान तम्बू के नीचे खड़े होकर प्रर्दशन किया।

कोलकाता, 14 सितम्बर। पश्चिम बंगाल में प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसीडेंट द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। जूनियर डॉक्टरों ने पीएम और राष्ट्रपति से आरजी कर अस्पताल के मामले में दखल देने की गुहार लगाई है। डॉक्टरों ने चार पेज के पत्र में देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से न्याय की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में जूनियर डॉक्टर 35 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी तक तीन बार डॉक्टरों से बातचीत के लिए बुलाया था। लेकिन डॉक्टरों ने कुछ शर्तें रख दीं, जिसके चलते यह बातचीत नहीं हो पाई है। वहीं, ममता बनर्जी ने इस्तीफे की पेशकश तक कर डाली, लेकिन डॉक्टर टस से मस नहीं हुए हैं।

जूनियर डॉक्टरों ने चार पेज का पत्र लिखा है। इस पत्र को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को भी भेजा गया है। इस पत्र में लिखा गया है कि आप देश का मुखिया हैं। ऐसे में यह मामला आपके सामने रख रहे हैं। हम अपने उस सहयोगी के लिए न्याय चाहते हैं जो एक बेहद घृणित अपराध की शिकार हो गई है। ऐसा होने के बाद हम हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग के तहत बिना किसी डर और आशंका के जनता की सेवा कर सकेंगे। पत्र में डॉक्टरों ने लिखा है कि इस मुश्किल समय में आपका दखल हम सभी के लिए रोशनी की किरण की तरह से काम करेगा। आप ही हैं जो हमें हमें चारों ओर से घिरे अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएंगे। आंदोलनकारी डॉक्टरों में शामिल अनिकेत महतो ने बताया कि पत्र का मसौदा इस महीने की शुरुआत में तैयार किया गया था और इसे गुरुवार रात भेजा गया।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आर जी कर अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद हड़ताल जारी है। जूनियर डॉक्टरों ने बारिश और अन्य चीजों की की परवाह किए बिना स्वास्थ्य भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं।

सुपरस्टार विजय फिल्मी दुनिया छोड़कर राजनीति में अपना करियर बनाएंगे

- सुपरस्टार विजय ने 30 साल के अपने फिल्म करियर में 68 फिल्में की हैं तथा उनमें से अधिकतर बड़ी हिट साबित हुईं हैं।

चेन्नई, 14 सितम्बर। तमिल एक्टर थलपति विजय जल्द ही अपना फिल्मी करियर छोड़कर राजनीति में अपना करियर बनाएंगे। लेकिन उससे पहले बैंगलुरु स्थित डिस्ट्रीब्यूशन हाउस केवीएन प्रोडक्शंस ने शुक्रवार को घोषणा की कि उन्होंने एक और फिल्म साइन की है। फैंस इस बात से एक्साइटेड हैं कि एक्टर अपनी नवगठित पार्टी, तमिलगा वेट्री कजगम के साथ राजनीति में जाने से पहले अपनी 69वीं फिल्म पूरी करेंगे और ये उनकी आखिरी फिल्म भी होगी।

शुक्रवार को, केवीएन प्रोडक्शंस ने विजय की आखिरी फिल्म के बारे में अपने एक्स पर अपडेट दिया। उन्होंने सबसे पहले विजय का चेहरा दिखाए बिना उनकी हिट फिल्मों के सीन्स का एक वीडियो शेयर किया और लिखा, "5 मणि-कु संधिप्पोम नानबा नानबी। हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमारी पहली तमिल फिल्म है। यह एक उत्सव है। यहां तक कि उत्सव का भी अपना इतिहास है।' बाद में, उन्होंने घोषणा की, "थलपति के लिए प्यार। हम सभी आपकी फिल्मों के साथ बड़े हुए हैं और आप हर कदम पर हमारे जीवन का हिस्सा रहे हैं। 30 वर्षों से अधिक समय तक हमारा मनोरंजन करने के लिए थलपति को धन्यवाद।" उन्होंने इस दौरान फैंस के साथ विजय की बातचीत का भी एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में उनके फैंस उनकी फिल्मों से उनके जुड़ाव के बारे में भी बात करते नजर आ रहे हैं। प्रोडक्शन हाउस ने कहा कि प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा बाद में की जाएगी।

'वरिष्ठ विपक्षी नेता ने मुझे प्र.मंत्री पद का ऑफर दिया था'

गडकरी ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले उनके समक्ष यह ऑफर आया था

- गडकरी ने मीडिया को संबोधित करते हुये कहा, "मैंने नेता को बताया कि मैं एक विचारधारा और विश्वास का पालन करने वाला व्यक्ति हूं। मैं एक ऐसी पार्टी में हूँ जिसने मुझे वह सब कुछ दिया है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कोई भी प्रस्ताव मुझे लुभा नहीं सकता।"
- उन्होंने कहा, 'मैंने उनसे साफ तौर पर कहा कि मैं कुछ सिद्धांतों और विश्वासों के साथ बड़ा हुआ हूं और मैं उनसे समझौता नहीं करूंगा।'

नई दिल्ली, 14 सितम्बर। केंद्रीय परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता ने उनके सामने प्रधानमंत्री पद का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। पत्रकारिता पुरस्कार समारोह के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा, "मैंने नेता से कहा कि मैं एक विचारधारा और विश्वास का पालन करने वाला व्यक्ति हूं। मैं एक ऐसी पार्टी में हूं जिसने मुझे वह सब कुछ दिया है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कोई भी प्रस्ताव मुझे लुभा नहीं सकता।'

हालांकि, नितिन गडकरी ने विपक्षी नेता का नाम नहीं बताया और न ही घटना के बारे में डिटेल से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2024 के आम चुनावों से पहले एक वरिष्ठ विपक्षी नेता ने मुझसे संपर्क किया था। उस समय माना जा रहा था कि बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी और सरकार बनाने के लिए उसे कुछ विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत हो सकती है। उन्होंने कहा, 'मैंने उनसे साफ तौर पर कहा कि मैं कुछ सिद्धांतों और विश्वासों के साथ बड़ा हुआ हूं और मैं उनसे समझौता नहीं करूंगा।'

उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बीजेपी की 240 सीटें ही आईं, जिसके बाद टीडीपी, जेडीयू जैसे दलों की मदद से गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत हासिल हुआ था।

इस बार कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने इंडिया अलायंस बनाया, जिसने एक साथ मिलकर देशभर में चुनाव लड़ा। इसका असर यह हुआ कि एन.डी.ए. के लिए 400 पार का दावा करने वाली भाजपा बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई। हालांकि, फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने।

अशोक गहलोत के सब्सिडी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्टाम्प ड्यूटी और कन्वर्ज़न चार्जेज़ में 75-75 प्रतिशत छूट दी जायेगी। इसमें से भी 25 प्रतिशत शुल्क की भरपाई पुनः कर दी जायेगी। इसी प्रकार लैंड टैक्स, विद्युत शुल्क, बाजार अथवा मंडी टैक्स के साथ ब्याज सब्सिडी में छूट दी जायेगी। निर्माण, एम.एस. एम.ई., लॉजिस्टिक तथा उभरते उद्योगों को ब्याज में सब्सिडी, टर्म लोन में राहत, ग्रीन इंसेंटिव, केपिटल सब्सिडी, टर्न ओवर लिंक सब्सिडी, इन्वैस्टमेंट सब्सिडी, कल्स्टर बेनेफिट समेत कई तरह की छूट देने के वायदे किए गए थे। इसी प्रकार एम.एम.एम.ई. (मध्यम दर्जे) कंपनियों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी (रोजगार सृजन छूट) देने की बात कही गई थी।

मजेदार तथ्य यह है कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में रिप्स-2022 की घोषणा तो की गई, लेकिन इसके प्रक्रिया सम्बंधी दिशानिर्देश बनाने का कोई काम नहीं हुआ। ऐसे में इन कंपनियों व उद्योगों को यह सब्सिडी और छूट किस प्रकार दी जायेगी, इसके बारे में कभी ना तो अशोक गहलोत साफ-साफ बता पाए और ना ही उनकी सरकार ने कोई सब्सिडी अथवा छूट जारी की। उधर जिन निवेशकों ने करोड़ों रुपये लगाकर राजस्थान में अपने उद्योग अथवा व्यापार स्थापित किए, वह आज आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। पिछले करीब 2 सालों में इन निवेशकों को राज्य सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिलने के कारण तथा अशोक गहलोत सरकार की झूठी और थोथी उद्योग राहत की घोषणाओं के चलते राजस्थान में निवेश के विपरीत माहौल भी बना।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान में भाजपा की नई सरकार बनने के बाद जो बजट सत्र हुआ, उसमें एक भी दिन अशोक गहलोत सदन की कार्यवाही में शामिल होने नहीं पहुंचे। इस वजह से उन्हें पिछली कांग्रेस सरकार के झूठे वादों और नाकामियों पर कोई जवाब नहीं देना पड़ा।

हालांकि वह अपनी "स्लिप डिस्क और पीठ दर्द" के चलते बिस्तर पर लेटे-लेटे और सोशल मीडिया पर नई सरकार के विदेशी निवेश के दौरे पर तंज कसने और अखबारों में फोटो छपवाने से नहीं चूके। मीडिया ने इनके आरोपों और कथनों को ज्यों का त्यों प्रकाशित तो किया, लेकिन उनकी सरकार के कार्यकाल में उद्योग निवेश को लेकर किए गए झूठे वादों पर सवाल नहीं उठाए।

'विनेश फोगाट खुद को अयोग्य ठहराये जाने के खिलाफ कोई अपील ही नहीं करना चाहती थीं'

इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से विनेश फोगाट का केस लड़ने वाले वकील हरीश साल्वे ने यह दावा किया

- हरीश साल्वे ने कहा, इंटरनैशनल ओलंपिक एसोसिएशन के फैसले के खिलाफ हमारी ओर से विनेश फोगाट को स्विस आर्बिट्रेशन सैन्टर में अपील करने की पेशकश की गई थी, लेकिन, फोगाट ने इस मामले में हमें कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी तो फिर हम कर भी क्या सकते थे।
- हरीश साल्वे ने कहा, हमें फोगाट का केस लड़ने के लिए दस्तावेजों व मामले को समझने के लिए फोगाट के वकीलों की ओर से सहयोग की आवश्यकता थी, लेकिन, उनके वकीलों ने कोई सहयोग नहीं किया, बाद में उनके वकीलों से पता चला कि फोगाट आगे अपील ही नहीं करना चाहती।

नई दिल्ली, 14 सितम्बर। वकील हरीश साल्वे ने पेरिस ओलंपिक को लेकर दावा किया है कि विनेश फोगाट चाहती ही नहीं थीं कि खेल पंचाट में उनके खिलाफ लिए गए फैसले को हम चुनौती दें। दरअसल, पेरिस ओलंपिक में पहलवान विनेश फोगाट को 7 अगस्त को पेरिस ओलंपकि में महिलाओं के 50 किग्रा फ्रीस्टाइल फाइनल के ठीक पहले 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के चलते अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसके कारण पहलवान विनेश फोगाट फाइनल से बाहर हो गई थीं। ओलंपिक के इतिहास में यह पहली बार था, जब भारत की कोई महिला पहलवान ओलंपिक के फाइनल में पहुंची हो।

हरीश साल्वे का यह बयान विनेश के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि जब ओलंपिक संघ ने उनको फाइनल के ठीक पहले अयोग्य घोषित किया तो उन्हें भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से कोई समर्थन नहीं मिला। विनेश ने कहा था कि हमारे जो वकील थे वह उस फैसले को लेकर पहले से ही उदार दिख रहे थे। इन सभी कारणों से ही उन्हें ओलंपिक में भारत का महिला पहलवानी का पहला गोल्ड या रजत पदक नहीं मिल सका। हालांकि, भारतीय ओलंपिक संघ और विनेश फोगाट की तरफ से इस फैसले के खिलाफ अपील की गई थी, जिसमें हरीश साल्वे ने ही वकील के रूप में उनका प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया और विनेश को बिना पदक के ही वापस लौटना पड़ा।

टाइम्स नाउ को दिए अपने एक इंटरव्यू में हरीश साल्वे ने बताया कि हमारी पेशकश के बाद भी विनेश फोगाट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती नहीं देना चाहती थीं। हालांकि बाद में हमें अपील देने लायक सभी दस्तावेज और जानकारी मिल गई, जिसके बाद हमनें कड़ा संघर्ष किया। लेकिन हमारी अपील को खारिज कर दिया गया। मैंने उन्हें यह भी बताया कि हम मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ दिए गए इस फैसले को लेकर स्विस अदालत में चुनौती दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बाद में उनके वकीलों नें मुझे बताया कि वह इसे आगे नहीं ले जाना चाहती। साल्वे ने आरोप लगाया कि विनेश फोगाट के वकीलों में तालमेल की कमी थी, ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा नियुक्त की गई एक बहुत बेहतर लॉ फर्म को कुछ वकीलों ने कहा कि हम आपके साथ कुछ भी साझा नहीं करेंगे। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 के दौरान महिलाओं की फ्रीस्टाइल कुश्ती के 50 किलोग्राम वर्ग में फाइनल के दिन ही 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

जलजीवन मिशन में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

टैंडर डालने का उसका उद्देश्य एक ही था और वह था मेघा इंजीनियरिंग के टैंडर को प्रतिस्पर्धात्मक दिखाना।

तीनों पैकेज में दोनों फर्मों की रेटों का विवरण समझिए:-
राशि करोड़ रुपए

पैकेज	सरकार का ऑफर	रामकी इंफ्रा	मेघा इंजी.	मेघा संशोधित	% ऊपर
1	3913	5322	5205	5205	33
2	1807	2549	2494	2494	38
3	2066	2996	2872	1901	(-) 8
योग	7786	10867	10571	9600	23

गहलोत सरकार ने जून 2023 में निविदाएं आमंत्रित कीं और अगस्त 2023 में निविदाएं खोलकर प्रोसेस कीं। चाहे उन्होंने अनुमोदित नहीं कीं लेकिन खेल तो वे कर गए, क्योंकि 'मेघा इंजीनियरिंग को पूरा अवसर मिल गया कि वह इस 23 प्रतिशत ऊपर की 2000 करोड़ की राशि से नेताओं, अफसरों को खरीद सके। सवाल यह उठता है कि:-

- एच.ए.एस. मॉडल में कंपनी निर्माण अवधि (4 साल) पूरी होने के 20 साल बाद की कीमत को आंख मींचकर भरती है, क्योंकि, न उसे पता और न सरकार को पता कि 2048 की स्थिति क्या होगी।
- जब सरकार के पास देने को पैसे नहीं थे तो आने वाली सरकारों पर बोझ डालकर आधी अधूरी योजना का काम शुरू करके जनता को क्यों मूर्ख बनाया जा रहा था।
- जनता को तो ये भी नहीं मालूम कि कुल लागत का 40 प्रतिशत भुगतान फर्म को अगले चार साल में होगा और बचे हुए 60 प्रतिशत का भुगतान अगले 20 सालों में किश्तों में होगा, लेकिन, सरकार कंपनी को बैंक ब्याज दर से 2 प्रतिशत ज्यादा ब्याज देगी। सवाल है, आखिर क्यों, जबकि पूरी योजना के 80 प्रतिशत भाग का अभी अता-पता ही नहीं है।
- रेटों के ऊपर दिए विवरण से साफ है कि सरकार के एस्टीमेट से केवल दो महीने में 33 और 38 प्रतिशत ऊंची दर हो गई जो मिलीभगत के बिना संभव नहीं है।
- पूरे टेंडर की सबसे बड़ी शर्त, जिसका लाभ मेघा इंजीनियरिंग जरूर उठाएगी, वो है कि कंपनी अपनी मनमर्जी से परियोजना की डिज़ाइन बदल सकती है, अर्थात् पाइप, नहर, बांध आदि के साइज़ में घटत भी कर सकती है।

कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकलता है कि अशोक गहलोत ने मेघा इंजीनियरिंग को काम दिलाने के लिए सभी तरह के प्रभाव का इस्तेमाल किया और हजारों करोड़ का घोटाला किया। इसका खुलासा तो सी.ए.जी. ऑडिट या सी.बी.आई. जांच से ही संभव है।

सरकार ने ...

सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क की दर 12.5 प्रतिशत से बढ़कर 32.5 प्रतिशत हो गयी है।

मेव समाज ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद दिल्ली चले गए। जहाँ जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया।

ज़ुबेर खान ने एक साल पहले लिवर ट्रांसप्लांट कराया था। लोकसभा के चुनाव में अधिक भागदौड़ से तकलीफ बढ़ गई थी, उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। करीब 15 दिन पहले मेदांता अस्पताल (गुरुग्राम, हरियाणा) के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उसके बाद बीच-बीच में जयपुर ले जाकर उनका इलाज कराया गया। बाद में ढ़ाई पेड़ी (अलवर शहर) में खुद के घर में ही आई.सी.यू. तैयार कराया था।

ज़ुबेर खान जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी दिल्ली के छात्रसंघ अध्यक्ष रहे थे। उस दौरान उनकी दिल्ली में रोड पर पैंफलेट लगाते समय राजीव गांधी से मुलाकात हुई थी।

उनसे प्रभावित होकर राजीव गांधी ने उनको एन.एस.यू.आई. का राष्ट्रीय सचिव बनाया था। तभी वे गांधी परिवार के नजदीक आ गए थे। फिर, उनको 1993 में टिकट दिया गया था। राजीव गांधी के बाद उन्होंने यू.पी. में प्रियंका गांधी के साथ खूब काम किया है। प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव रहने के दौरान ज़ुबेर खान उनके साथ सह प्रभारी सचिव थे।

'निवेशकों ने प्रदेश की डबल इंजन सरकार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- मदन राठौड़ ने कहा, प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार अस्थिर थी, कुर्सी बचाने के लिए होटलों में डेरा डाला था तो निवेशकों को भरोसा कैसे दिलाती?

लर्निंग के लिए एक महाविद्यालय भी खोला जाएगा। इसके साथ ही 25 आई.ए.एस. अधिकारियों को विश्व के 25 बड़े देशों के साथ समन्वय के लिए लगाया जाएगा, जो राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की अर्थ व्यवस्था को अगले पांच साल में दोगुना करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। राइज़िंग राजस्थान के लिए इन्वैस्ट समिट की तरह ग्लोबल समिट किया जाएगा। इसमें विदेशों में जाकर इन्वैस्टमैंट के लिए निवेशकों को तैयार किया जाएगा। इस दिशा में राजस्थान सरकार 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में भी राईज़िंग राजस्थान रोड शो का आयोजन करेगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाएं है। सभी क्षेत्रों में अपार संभावनाओं के साथ राजस्थान की डबल इंजन सरकार पर देश-विदेश के निवेशकों ने विश्वास जताया है। भाजपा की सरकार ने भी उन्हें सुरक्षा के साथ समुचित संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए आश्वस्त किया है। भाजपा जो कहती है उसे पूरा करने पर यकीन करती है। कार्य करने की इच्छा शक्ति हो तो ईश्वर भी आप की मदद करने को तैयार हो जाता है। भाजपा की सरकार बनने के साथ ही ऊर्जा और पानी के क्षेत्र में कार्य करने की योजनाएं बनाई गई।

इस दिशा में जहां 32 हजार मेगावाट ऊर्जा के एमओयू साइन किए गए वहीं पानी के लिए ईआरसीपी और यमुना जल समझौता जैसे वर्षों से लंबित कार्य को पूरा करने की दिशा में कार्य किया गया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराष्ट्र में इन्वैस्ट समिट के बाद "कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया" का सपना का साकार करने के उद्देश्य से दक्षिण कोरिया और जापान में जाकर निवेशकों को आमंत्रित किया है। जबकि राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने निवेशकों को आमंत्रित तो किया लेकिन निवेशकों ने उन पर भरोसा तक नहीं जताया। पूर्ववर्ती सरकार के राज में प्रदेश की सरकार अस्थिर थी, गहलोत सरकार कुर्सी बचाने के लिए होटलों में बैठी रही।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विदेशी निवेशकों को सुरक्षा के साथ सुविधाएं, संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए आश्वस्त किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित भाजपा सरकार प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रयासरत है। ऐसे में हम सभी को मिलकर मुख्यमंत्री के इस प्रयास को पूरा करने के लिए कार्य करना चाहिए।

उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राजस्थान को विकसित राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकार बनने के साथ ही इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया था। सीएम शर्मा ने विदेशी निवेशकों के साथ कई दौर की बैठके की और उत्साहित निवेशकों को राधे-राधे के रंग में रंग दिया।

कार्यक्रम में मंच पर भाजपा राजस्थान के प्रभारी डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष अशोक परनामी, सीपी जोशी, भाजपा महामंत्री एवं सांसद दामोदर अग्रवाल, भाजपा महामंत्री जितेंद्र गोठवाल उपस्थित थे।

एयरपोर्ट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में मंत्री मंडल के सदस्य, सासंद, विधायक, भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, एससी-एसटी मोर्चा के साथ सभी मोर्चा, प्रकोष्ठ और विभागों के संयोजक एवं सह संयोजकों ने मुख्यमंत्री का स्वागत अभिनंदन किया।

अशोक गहलोत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संबंध हैं।

गहलोत को ए.आई.सी.सी. कोषाध्यक्ष अजय माकन तथा प्रताप सिंह बाजवा के साथ हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

सूत्रों का कहना है कि माकन को संभवतः गहलोत पर नज़र रखने के लिए तथा उन्हें बैलैंस करने के लिए लाया गया है, क्योंकि, दोनों का आपसी बैर का इतिहास रहा है।

इसके अलावा दोनों का बैलैंस करने के लिए प्रताप सिंह बाजवा को नियुक्ति दी गई है। बाजवा, हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब के हैं तथा हरियाणा में बड़ी संख्या में सिख रहते हैं।

गहलोत के पास कोई खास काम नहीं होगा, चूंकि, चुनावों का सारा कंट्रोल भूपेन्दर सिंह हूडा के हाथों में है। गहलोत इस मौके का इस्तेमाल करके खुद को और अधिक महत्पूर्ण पद पर लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन, पूर्व मुख्यमंत्री के लिए यह एक लंबी और कठिन राह साबित होगी।

प्र.मंत्री मोदी के सी.जे.आई...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को शक तो होगा।

वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि सी.जे.आई. ने कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच "शक्ति के पृथक्करण" से समझौता किया है। उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा सी.जे.आई. की स्वतंत्रता पर से भरोसा उठ गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को सी.जे.आई. की स्वतंत्रता के साथ हुए इस समझौते का विरोध करना चाहिए।

भाजपा के सम्बित पात्रा ने विपक्ष पर जवाबी प्रहार किया कि ०"'न्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में तत्कालीन सी.जे.आई. ने भाग नहीं लिया था। उन्हें प्रधानमंत्री के सी.जे.आई. से मिलने पर आपत्ति नहीं है बल्कि गणपति पूजा पर है।

पात्रा ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता राजनीति कर रहे हैं। मुझे हैरानी है कि अगर प्रधानमंत्री सी.जे.आई. से मिलते हैं तो आप आपत्ति करते हैं पर जब राहुल गांधी अमेरिका सांसद इल्हान उमर से मिलते हैं, जो पाक अधिकृत कश्मीर के हैं, तो आपका कोई आपत्ति नहीं होती।"

भाजपा के महासचिव बी.एल. संतोष ने भी विपक्ष की आलोचना की और कहा कि वामपंथी रुझान वाले नेता धार्मिक कार्यक्रम से परेशान हैं। शिवसेना के मिलिन्द देवड़ा ने भी मोदी के इस विज़िट को अनावश्यक उछाले जाने की आलोचना की और कहा कि वर्ष 2009 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने इफ्तार पार्टी की थी, जिसमें तत्कालीन सी.जे.आई. के.सी.बालकृष्णन ने भाग लिया था।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालयः सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालयः आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालयः-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908